



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, २५ मार्च, १९९७/४ चैत्र, १९१९

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-१७१००४, २५ मार्च, १९९७

संख्या विधान/विधेयक/१-१२/९७-वि० एस०.— हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, १९७३ के नियम १३५ के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९९७

(1997 का विधेयक संख्यांक 2) जो आज दिनांक 25 मार्च, 1997 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुर
स्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनाओं असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-

सचिव,

हि० प्र० विधान सभा

1997 का विधेयक संख्यांक 2.

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1997

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1997 है।

संक्षिप्त
नाम और
प्रारम्भ।

(2) यह 10 जनवरी, 1997 को प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1994 का 13

2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 10 का
संशोधन।

“(3) नगरपालिका में इस धारा के अधीन सीधे निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के अतिरिक्त, पूर्णतः या अंशतः नगरपालिका क्षेत्र में समाविष्ट निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधान सभा के सदस्य, भी सदस्य होंगे और राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को भी, जो तीन से अधिक नहीं होंगे, सदस्य के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगी :

परन्तु इस उप-धारा में निर्दिष्ट व्यक्तियों और नगरपालिका परिषद् की दशा में कार्यपालक अधिकारी तथा नगर पंचायत की दशा में सचिव को नगरपालिका की सभी बैठकों में उपस्थित होने तथा विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।”

3. मूल अधिनियम की धारा 211 में, उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

धारा 211
का संशोधन

“(2) जहां निर्माण का स्वामी अपने वन्द किए गए कार्य या उस द्वारा पूर्ण किए गए कार्य के पश्चात् संशोधित रेखांक प्रस्तुत करता है और उसमें मंजूर रेखांक से विचलन है, तो नगरपालिका, उप-धारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष या साधारण निदेशों के अध्यक्षीन विचलन के मामलों का, मंजूर रेखांक से दस प्रतिशत तक प्रशमन कर सकेगी :

परन्तु जहां संशोधित रेखांक में—

(i) किसी सरकारी भूमि या नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि; या

(ii) किसी लोक सड़क, मार्ग, पथ या नाली को आच्छादित करते हुए; या

(iii) हिमाचल प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1968 के उपबन्धों का 1969 का 21 उल्लंघन करते हुए, निर्माण का परिनिर्माण अन्तर्वर्तित है;

वहां नगरपालिका मंजूर रेखांक से विचलन का प्रशमन नहीं करेगी।

(2क) उप-धारा (2) के अधीन नगरपालिका के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, नगरपालिका द्वारा आदेश पारित करने से तीस दिन के भीतर और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, उपायुक्त को अपील कर सकेगा।

(2ख) उप-धारा (2क) के अधीन अपील में उपायुक्त के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, उपायुक्त द्वारा किए गए आदेश से तीस दिन के भीतर और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।

(2ग) अपील प्राधिकारी, कारणों को अभिलिखित करते हुए, उप-धाराएं (2क) और (2ख) में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के पश्चात् भी अपीलों दाखिल करने की अनुज्ञा दे सकेगा और उक्त उप-धाराओं के अधीन तीस दिन की अवधि की संगणना करने के लिए, आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की प्रमाणित प्रतियां उपाप्त करने के लिए व्यतीत हुआ समय अपवर्जित किया जाएगा।

(2घ) राज्य सरकार उप-धाराएं (2), (2क) और (2ख) में किसी बात के होते हुए भी, अत्यधिक कठिनाई के असाधारण मामलों में, मंजूर रेखांक से विचलन के मामलों का प्रशमन कर सकेगी।”

1997 के
अध्यादेश
संख्यांक 2
का निरसन।

4. (1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का निरसन होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस समय हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के अधीन आसीन विधान सभा के सदस्य नगरपालिकाओं और नगर पंचायत के सदस्य नहीं हैं और इस कारण वे आने चुनाव क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली नगरीय स्थानीय निकायों की दिन प्रतिदिन के विकासात्मक क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। विधान सभा में नगरपालिकाओं के हितों के प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें नगरपालिकाओं में सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाए। इसके अतिरिक्त मंजूर की गई निर्माण रेखांक से विचलन के नियमितिकरण में जनसाधारण द्वारा अनुभव की जाने वाली अनिश्चितता और कठिनाई को दूर करने की अति आवश्यकता है। इस कारण उक्त अधिनियम में शीघ्र संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) में तत्काल संशोधन किया जाना अपेक्षित था। अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 2) 8 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित किया गया और इसे 10 जनवरी, 1997 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था। उक्त अध्यादेश को अब नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

जय बिहारी लाल खाची,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख 25 मार्च, 1997

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3, अधिनियमित किए जाने पर राज्य सरकार को अपीलें दाखिल करने की रीति अधिकथित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करेगा। यह प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 2 of 1997.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT)
BILL, 1997

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-eighth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title
and com-
mencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 1997.

(2) It shall and shall be deemed to have come into force on the 10th day of January, 1997.

Amendment
of section
10.

2. For sub-section (3) of section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), the following sub-section shall be substituted, namely:—

13 of 1994

“(3) In a municipality, in addition to persons chosen by direct election under this section, the Members of the State Legislative Assembly, representing constituencies which comprise wholly or partly in municipal area, shall also be the members and the State Government may, by notification, also nominate as members, not more than three persons, having special knowledge or experience of Municipal administration :

Provided that the persons referred to in this sub-section and the Executive Officer in case of Municipal Council and Secretary in the case of Nagar Panchayat, shall have the right to attend all the meetings of the municipality and to take part in discussion therein but shall not have the right to vote.”

Amendment
of section
211.

3. In section 211 of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

“(2) Where the owner of the building submits the revised plan, after the work has been stopped by him or the work is completed by him and there are deviations from the sanctioned plan, the municipality may, subject to the special or general directions of the State Government under sub-section (3), compound the cases of deviations upto 10% from the sanctioned plan :

Provided that where the revised plan involves erection of building—

(i) on any Government land or the land vested in a municipality or a local authority; or

(ii) by covering any public road, street, path or drain; or

(iii) by contravening the provisions of the Himachal Pradesh Roadside Land Control Act, 1968;

21 of 1969

the municipality shall not compound deviations from the sanctioned plan.

(2A) Any person aggrieved by the decision of the municipality under sub-section (2), may, within thirty days from the passing of the order by the municipality and in such manner as may be prescribed, appeal to the Deputy Commissioner.

(2B) Any person aggrieved by the decision of the Deputy Commissioner in appeal under sub-section (2A), may, within thirty days from the order made by the Deputy Commissioner and in such manner as may be prescribed, appeal to the State Government.

(2C) The appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, allow the appeals to be filed after the expiry of the period of thirty days specified in sub-sections (2A) and (2B) and for calculating the period of thirty days under the said sub-sections, the time spent in procuring the certified copies of the orders to be appealed against shall be excluded.

(2D) Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (2A) and (2B), the State Government may, in exceptional cases of extreme hardship, compound the cases of deviations from sanctioned plans."

4. (1) The Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 1997 is hereby repealed.

Repeal of
Ordinance
No. 2 of
1997.

(2) Notwithstanding the repeal of the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 1997 anything done or action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present the sitting Members of the Legislative Assembly are not the members of the Municipal Councils and Nagar Panchayats, under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and as such they are unable to gain knowledge about the day to day developmental activities of the Urban Local Bodies falling within their constituencies. For effective representations of the interests of municipalities in the Assembly it is necessary that they may be associated as members in the municipalities. Apart from this there is also urgent need to remove the uncertainty and hardship being experienced by the public in regularisation of deviations from the sanctioned building plans, as such it has become necessary to make immediate amendments in the aforesaid Act.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the amendments in the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) was required to be made urgently, the Governor, Himachal Pradesh, promulgated under clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 1997 (Ordinance No. 2 of 1997) on the 8th January, 1997 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra ordinary) dated 10-1-1997. Now the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the said Ordinance without any modification.

JAI BIHARI LAL KHACHI,
Minister-in-charge.

SHIMLA :
The 25th March, 1997.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 3, of the Bill when enacted will empower the State Government to make rules to lay down the manner in which appeals will be filed. The delegation is essential and normal in character.